नियमावली - 4

कार्यों के निर्वाहन के लिए निर्धारित मानदंड [धारा 4 (1) (बी) (iv)] कुछ मानदंड नीचे दिए गए हैं:

चित्रण

कार्यकलाप	समय सीमा / मानदंड	टिप्पणी
I) जाँच पड़ताल		
1) एफआईआर का पंजीकरण 2) साक्षी की परीक्षा 3) अपराध स्थल पर जांच अधिकारी का दौरा 4) सबूत का संग्रह 5) साइट प्लान तैयार करना 6) अभियुक्तों की गिरफ्तारी 7) स्वीकारोक्ति की रिकॉर्डिंग 8) पुलिस / न्यायिक हिरासत रिमांड प्राप्त करना 9) खोज 10) जब्ती 11) केस डायरी आदि तैयार करना 12) चार्जशीट दाखिल करना	भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अनुसार	
II) पुलिस नियंत्रण कक्ष		
ईआरएसएस-112, दिल्ली प्रणाली में सार्वजनिक सहायता के लिए 1090, 1091, 1096, 1291, 155270, और 155271 और अन्य प्रत्यक्ष हेल्पलाइनों के साथ-साथ 122 चैनलों (एसीडी द्वारा सूचित 450 तक विस्तार योग्य) वाली 15 पीआरआई लाइनें हैं। पीसीआर वैन के लिए औसत प्रतिक्रिया समय आज तक लगभग 07:00 मिनट है		

और यह सड़क और यातायात की स्थिति पर भी निर्भर करता है।

III) सतर्कता: -

सतर्कता शाखाएं विभिन्न प्राधिकरणों के माध्यम से और सीधे जनता से बड़े पैमाने पर शिकायतें प्राप्त करती हैं। सीएमटीएस, सीपीजीआरएमएस, सीवीसी, एलजी लिसनिंग पोस्ट और पीजीएमएस कार्यक्रम के कामकाज पर लगभग इन शिकायतों की ऑनलाइन निगरानी की जा रही है। शिकायतें, जो प्रकृति में गंभीर हैं, सतर्कता पूछताछ के माध्यम से सतर्कता शाखा द्वारा निपटा दी जाती हैं।

क्र.सं.	कार्यकलाप	समय सीमा	टिप्पणी
1	शिकायत और डायरी मिली	दो दिन	बड़ी संख्या में शिकायतें प्राप्त होने के कारण और उसी को चिह्नित करने में समय लगता है।
2	अद्वितीय नंबर बनाने के लिए कंप्यूटर प्रकोष्ठ में शिकायत जाएगी	एक दिन	-
3	जवाब प्रस्तुत करने के लिए शिकायत सम्बद्ध प्रधान सहायक के पास जाएगी	उसी दिन	-
4	जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए शिकायत ईओ के पास जाती है	उसी दिन	-
5	जांच ईओ द्वारा पूरी की जाएगी	तीन सप्ताह	-
6	जांच रिपोर्ट वरिष्ठ अधिकारी को सौंपी जाएगी	उसी दिन	-
7	कार्यवाई करने के लिए पूछताछ वापस मिली	एक दिन	-
8	प्रधान सहायक द्वारा की गई कार्रवाई	आदेशों के अनुसार उसी दिन। 2-3 दिनों के भीतर कार्यवाई हो सकती है। डीई के मामले में एक और सप्ताह होगा।	
9	आवेदक को जानकारी	4 सप्ताह के बाद	

IV) यातायात :-

क्र..नहीं	गतिविधि	कार्रवाई का स्तर	निर्धारित समय - सीमा
1.	यातायात का विनियमन	सभी यातायात अधिकारियों/कर्मियों एवं सिग्नलों द्वारा	चौबीसों घंटे
2.	सूचना – प्रवाह चार्ट नीचे दिया गया है:- I. टैफिक अधिकारी को वोका ऐप (वॉयलेशन ऑन कैमरा ऐप) के माध्यम से उल्लंघन को पकड़ने के लिए ड्यूटी के विशेष बिंदु पर तैनात किया गया है। II. उल्लंघन की रिपोर्ट भी कैमरों के माध्यम से की जाती है। III. प्रहरी ऐप के माध्यम से जनता द्वारा ।	I. यातायात पुलिस II. आरएलवीडी शाखा	चौबीसों घंटे
3.	I. सभी उल्लंघन प्रमाणीकरण के लिए स्वचालित रूप से सर्वर पर भेजे जाते हैं। Voca के मामले में , उल्लंघन की जाँच सर्कल स्टाफ द्वारा की जाती है और रिपोर्ट अपराध नोटिस जनरेशन के लिए सर्वर पर भेजे जाते हैं। II. कैमरे और सार्वजनिक माध्यम से सूचित उल्लंघन की जांच आरएलवीडी शाखा द्वारा की जाती है।	I. सर्किल स्टाफ II. आरएलवीडी शाखा	चौबीसों घंटे
4.	वाहन पोर्टल पर रिकॉर्ड के अनुसार, एसएमएस या स्पीड पोस्ट के माध्यम से वाहन के पंजीकृत मालिक को भेजा जाता है।	I. कंप्यूटर शाखा II. सूचना शाखा	I. गैर-समझौता योग्य अपराधों के लिए 15 दिनों के भीतर II. समझौता योग्य अपराधों के लिए 30 दिनों के भीतर
5.	नोटिस प्राप्त होने पर	कंप्यूटर शाखा	2 से 3 दिन

	<p>उल्लंघनकर्ता समझौता सूचना शाखा राशि जमा कर सकता है</p> <p>I. दिल्ली यातायात पुलिस की वेबसाइट पर ऑनलाइन।</p> <p>II. नोटिस शाखा, यातायात पुलिस मुख्यालय, देव प्रकाश शास्त्री मार्ग, नई दिल्ली में डीडी/ चेक द्वारा</p> <p>III. सर्किल में ईचलान मशीन के माध्यम से</p>		
6.	<p>I. नॉन-कंपाउंडेबल नोटिस 15 दिनों के बाद न्यायालय को भेजे जाते हैं।</p> <p>II. कंपाउंडेबल नोटिस का भुगतान दिल्ली टैफिक पुलिस की वेबसाइट पर 90 दिनों के भीतर किया जा सकता है। उसके बाद इसे कोर्ट में भेजा जाता है।</p>	<p>एनआईसी के माध्यम से स्वचालित रूप से</p>	<p>I. नॉन-कंपाउंडेबल को 15 दिन बाद न्यायालय भेजा गया</p> <p>II. समझौता योग्य नोटिस 90 दिनों के बाद न्यायालय को भेजे जाते हैं</p>
7.	<p>शिकायत निवारण की सुविधा उपलब्ध है।</p> <p>उल्लंघनकर्ता एसएमएस/प्रिंटेड नोटिस प्राप्त होने के 15 दिनों के भीतर शिकायत दर्ज करा सकता है। इसकी जांच आरएलवीडी शाखा द्वारा की जाती है और उसके अनुसार कार्रवाई की जाती है।</p>	<p>I. आरएलवीडी शाखा</p> <p>II. कंप्यूटर शाखा</p>	15 दिनों के भीतर
v) विशेष शाखा			
<p>“दिल्ली पुलिस की विशेष शाखा का (एपीपी शाखा) पासपोर्ट सत्यापन अनुभाग ऑनलाइन प्राप्त पासपोर्ट के सत्यापन से सम्बंधित है। पासपोर्ट आवेदन पासपोर्ट सेवा केन्द्रों (पीएसके), क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालयों (आर प ओ) और सम्बंधित दूतावास/ वाणिज्य दूतावास से सीधे टैबलेट पर प्राप्त होते हैं जिन्हें आवेदको के सत्यापन के लिए जांच अधिकारी (ई. ओ.) को आवंटित किया गया है। सत्यापन पूरा करने के बाद, जांच अधिकारी सत्यापन रिपोर्ट अपलोड करता है और इसे</p>			

इंस्पेक्टर जोन को भेज देता है। उसके बाद इंस्पेक्टर जोन उचित सत्यापन के बाद उसे जोनल एसीपी को भेजता है। जो डीएससी (डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट) का उपयोग करके सत्यापन रिपोर्ट को मंजूरी देता है और रिपोर्ट क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय, विदेश मंत्रालय या संबंधित प्राधिकारी को सौंपता है। टैबलेट की शुरुआत के बाद से, पासपोर्ट सत्यापन को पूरा करना और 5 दिनों के भीतर संबंधित आरपीओ/प्राधिकरण को जमा करना आवश्यक है। प्रतिदिन औसतन 1800-2000 पासपोर्ट आवेदन ऑनलाइन प्राप्त होते हैं।

एपीपी शाखा "ओ" पास (अन्य देशों और अन्य राज्यों से सत्यापन क लिए प्राप्त पासपोर्ट आवेदन), एनओआरआई (भारत लौटने की कोई वाध्यता नहीं) और क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालयों, आरटीआई और ई-मेल से प्राप्त कार्यों की भी करती है। आवेदक इस कार्यालय की ई-मेल आईडी यानी dcp-splbranch-dl@nic.in और dpapp.sb@delhipolice.gov.in पर अपना फीडबैक भेज सकते हैं। वे अपने प्रश्न लैंडलाइन नंबर यानी 011-23230577 पर भी पूछ सकते हैं।

VI) विभागीय जांच प्रकोष्ठ

दिल्ली पुलिस में विभागीय जांच प्रकोष्ठ की स्थापना भारत सरकार गृह मंत्रालय , नई दिल्ली द्वारा आदेश संख्या 14014/41/85- यूटीपी, दिनांक 09/04/86 के तहत की गई थी। वर्तमान में यह 8^{वीं} मंजिल, थाना बाराखंभा रोड बिल्डिंग, नई दिल्ली, में कार्यरत है।

विभागीय जांच प्रकोष्ठ के कर्तव्य इस प्रकार हैं: -

1. सतर्कता जांच से उत्पन्न होने वाली विभागीय जांचों और ऐसी अन्य विभागीय जांचो, जिन्हें पुलिस आयुक्त द्वारा आवश्यक समझा जायें, समय- समय पर इस प्रकोष्ठ की कार्यात्मक शक्ति के आधार पर और अन्य प्रशासनिक आवश्यकताओं के अनुसार, का केंद्रीय रूप से संचालन करना।
2. विभागीय पूछताछ से संबंधित रिपोर्ट/ वापसी।
3. दिल्ली पुलिस के कर्मचारियों के लिए समय-समय पर "विभागीय जांच कैसे करें" पर प्रशिक्षण पाठ्यक्रम आयोजित करना।

विभागीय जांच के लिए प्राधिकार :-

(ए) दिल्ली पुलिस (दंड और अपील) नियम -1980 के नियम 14.4 के अनुसार अधीनस्थ रैंक के अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाई सक्षम प्राधिकारी द्वारा शुरू की जानी चाहिए। जिसके अनुशासनात्मक नियंत्रण के तहत संबंधित पुलिस अधिकारी को उस समय तैनात किया जाता है। जब अनुशासनात्मक कार्यवाई शुरू करने का निर्णय लिया जाता है।

(बी) जिला / इकाइयाँ दिल्ली पुलिस आयुक्त की पूर्वानुमति के बिना विभागीय जांच (Departmental Enquires) सीधे विभागीय जांच प्रकोष्ठ को नहीं भेज सकते है। इसे ध्यान मे रखते हुए, उपायुक्त जिला/ इकाई उन विभागीय जांचो को जिन्हें विभागीय जांच प्रकोष्ठ मे स्थानांतरित करना आवश्यक है, के सम्बन्ध मे उचित अनुरोध दिल्ली पुलिस आयुक्त को संबधित अतिरिक्त पुलिस आयुक्त/सयुक्त पुलिस आयुक्त/वेशेष पुलिस आयुक्त के माध्यम से भेज सकते हैं। हालांकि व्यापक मानदंड निर्धारित करना मुश्किल है जिसके आधार पर विभागीय जांच (Departmental Enquires) को विभागीय जांच प्रकोष्ठ मे स्थानांतरित किया जाये, इसे संबधित अधिकारियों के निर्णय पर छोड दिया जाना चाहिए। पर्यवेकशी अधिकारियों को शुरू की गई विभागीय जांच कि

बारिकी से निगरानी करने की आवश्यकता है और उचित मामलों में वे विभागीय जांच को स्थानांतरित करने के लिए स्वम करवाई शुरू कर सकते हैं।

समय सीमा / मानदंड

स्थायी आदेश संख्या Vig. & Pub. TPT/011/2022, के अनुसार, यदि संभव हो तो जांच अधिकारी दोषी पर आरोपों के सारांश की सेवा की तारीख से छह महीने की अवधि के भीतर विभागीय जांच पूरी करने का प्रयास करेगा। दिल्ली पुलिस (दंड और अपील) नियम, 1980, अधीनस्थ रैंक के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों यानि कांस्टेबल से इंस्पेक्टर तक लागू होते हैं।

VII) ईओडब्ल्यू

क्रम सं.	गतिविधि	निर्धारित समय - सीमा	टिप्पणी
1.	ऑनलाइन, डाक और हाथ से प्राप्त शिकायतें डायरी में दर्ज की गईं।	1-5 दिन	प्राप्त शिकायतों की संख्या बहुत अधिक होने के कारण उन्हें डायरी में दर्ज करने में समय लग सकता है।
2.	विशिष्ट नंबर के लिए शिकायतें शिकायत शाखा को भेजी गईं	1-5 दिन	बड़ी संख्या में प्राप्त शिकायतों के कारण यूनिट को इसका समाधान करने में समय लग सकता है।
3.	डीसीएसपी /ईओडब्ल्यू के समक्ष प्रस्तुत शिकायतों के अवलोकन के पश्चात उन्हें उनके अधीन कार्यरत संबंधित अनुभागों को भेजने के लिए कहा गया।	1-5 दिन	प्राप्त शिकायतों की संख्या बहुत अधिक होने के कारण उन्हें चिन्हित करने में समय लग सकता है।
4.	अनुभाग (एसीपी) में चिन्हित शिकायतें	एक ही दिन	विशिष्ट कारण से समय लग सकता है
5.	पूछताछ का समय	ललिता मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार कुमारी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य	चूंकि शिकायतें बहुत बड़ी हैं और कई पीड़ित हैं, इसलिए प्रत्येक संबंधित/संबंधित अधिकारी/व्यक्ति से संपर्क करने में काफी समय लग सकता है। इसे जल्द से जल्द पूरा करने के लिए हर संभव प्रयास किए जाते हैं।
6.	आवेदक को की गई कार्रवाई की जानकारी	जांच पूरी होने पर	जांच पूरी होने के तुरंत बाद। हालांकि, शिकायतकर्ता अपनी शिकायतों की प्रगति जानने के लिए कार्य दिवसों/घंटों के दौरान संबंधित जांच अधिकारी से संपर्क करने के लिए स्वतंत्र हैं।

VII) दिल्ली पुलिस अकादमी :-

क्र.स.	गतिविधिया	समय सीमा/मानदंड	टिप्पणी
1.	DANIPS का फाउंडेशन प्रशिक्षण	01 वर्ष	

2.	दिल्ली न्यायिक अधिकारी प्रशिक्षण	02 सप्ताह	
3.	Trg. on Drill and Etiquette of Asst. Communication officer of DCPW/MHA (Group non-Gazetted)	03 सप्ताह	
4.	निरक्षक व उप निरक्षक कंप्यूटर कि मूलभूत प्रशिक्षण	04 माह	
5.	प्रशिक्षु उप निरक्षक कि मूलभूत प्रशिक्षण (DP)	01 वर्ष	
6.	प्रशिक्षु उप निरक्षक कि मूलभूत प्रशिक्षण (अन्य राज्य व केन्द्र शासित प्रदेश)	11 माह	
7.	साहयक उप निरक्षक (Steno) कि मूलभूत प्रशिक्षण	04 माह	
8.	साहयक उप निरक्षक कि मूलभूत प्रशिक्षण (चंडीगढ़)	11 माह	
9.	प्रधान सिपाही (Min.) कि मूलभूत प्रशिक्षण	04 माह	
10.	अभ्यास (ड्रिल) प्रशिक्षक पाठ्यक्रम	09 माह	
11.	जेल प्रहरी तिहाड़ का मूलभूत प्रशिक्षण	04 माह	
12.	प्रशिक्षु सिपाही का मूलभूत प्रशिक्षण	09+01 माह	
13.	प्रशिक्षु सिपाही का मूलभूत प्रशिक्षण (अन्य राज्य व केन्द्र शासित प्रदेश)	09+01 माह	
14.	MTS का मूलभूत प्रशिक्षण	04 माह	
15.	उप निरक्षक का परमोशनल कोर्स	04 सप्ताह	
16.	साहयक उप निरक्षक का परमोशनल कोर्स	06 सप्ताह	
17.	प्रधान सिपाही का परमोशनल कोर्स	06 सप्ताह	